सुशील मुर्मू

बनाम

झारखंड राज्य

12 दिसंबर 2003

[दौरैस्वामी राजू और अरिजीतपसायत, जेजे]

दंड संहिता, 1860/आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 201, 302/354(3)-एक छोटे बच्चे की बलि-सिर काटकर फेंकना तालाब में बच्चा - विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की दंड सुनाई गई - उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की दंड की पुष्टि की शुद्धता की अभिनिर्धारित, तथ्यों के आधार पर, यह सही मामला है जिसे दुर्लभ से दुर्लभतम माना जाना चाहिए - इसलिए दोषसिद्धि और मृत्युदंड की दंड अभिनिर्धारित की गई है।

अपीलकर्ता द्वारा देवी काली के सामने एक 9 साल के बच्चे की बलि दी गई। अपीलकर्ता ने बच्चे का सिर काटकर तालाब में फेंक दिया। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भा.द.वि. की धारा 302 और 201 के तहत दोषी पाया और क्रमशः मृत्युदंड और 7 साल की कारावास की दंड सुनाई। उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की दंड की अधिपुष्टि किया ।

अपील में अपीलकर्ता ने प्रतिवाद किया कि अपीलकर्ता को दी गई मृत्युदंड की दंड को इस आधार पर आजीवन कारावास में बदल दिया जाए कि बच्चे की हत्या किसी हेतु से नहीं की गई थी; अपीलकर्ता एक अनपढ़ और आदिवासी था और अंधविश्वास से भरे माहौल में पला-बढ़ा था; और अपीलकर्ता को सुधारा जा सके।

राज्य ने प्रतिवाद किया कि अपीलकर्ता को उचित रीति से मृत्युदंड के दंड से दंदादिष्ट किया गया था, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जो स्पष्ट रूप से "दुर्लभतम" श्रेणी में आता है; अपीलकर्ता पर भी इसी तरह के अपराध के लिए आरोप लगाया गया था जो लंबित है।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 अपराध और दंड के बीच अनुपात का सिद्धांत न्यायसंगत रेगिस्तान का सिद्धांत है जो हर आपराधिक दंड की नींव के रूप में कार्य करता है जो उचित है। आपराधिक न्याय के सिद्धांत के रूप में, यह इस सिद्धांत से शायद ही कम परिचित या कम महत्वपूर्ण है कि केवल दोषियों को ही दंडित किया जाना चाहिए। वास्तव में आवश्यकता यह है कि दंड असंगत रूप से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो रेगिस्तान का एक स्वाभाविक परिणाम है, उसी सिद्धांत सेलेखापित होता है जो आपराधिक आचरण के लिए योग्य से अधिक किसी भी दंड के लिए निर्दोष को दंड देने की अनुमति नहीं देता है। जो अपराध के बिना दंड है. [712-एफ-एच]

1.2. आपराधिक कानून आम तौर पर प्रत्येक प्रकार के आपराधिक आचरण की दोषीता के अनुसार दायित्व निर्धारित करने में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करता है। यह आमतौर पर न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में दंड पर पहुंचने में कुछ महत्वपूर्ण विवेक की अनुमति देता है। न्यायाधीश संक्षेप में इस बात की पुष्टि करते हैं कि दंड हमेशा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए; फिर भी व्यवहार में दंडादेश बड़े पैमाने पर

अन्य विचारों से निर्धारित होते हैं।कभी-कभी, किसी दंड को सही ठहराने के लिए अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकता की पेशकश की जाती है। कभी उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयता, तो कभी उसके अपराध के दुखद परिणाम भी।अनिवार्य रूप से ये विचार दंड के आधार के रूप में उचित रेगिस्तान से विचलन का कारण बनते हैं और स्पष्ट अन्याय के मामले पैदा करते हैं जो गंभीर और व्यापक हैं। (713-ए-सी]

एडिगाअनम्मा बनाम ए.पी. राज्य, [1974] 4 एससीसी 443; बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1980] 2 एससीसी 684 और मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983] 3 एससीसी 470, निर्देशित किये गए ।

1.3. अपराध और दंड के बीच अनुपात एक ऐसा लक्ष्य है जिसका सैद्धांतिक रूप से सम्मान किया जाता है, और गलत धारणाओं के बावजूद, यह वाक्यों के निर्धारण में एक मजबूत प्रभाव रखता है। किसी भी गंभीर अपराध के लिए अधिकतम गंभीरता के दंड से कम की दंड को सहनशीलता का एक उपाय माना जाता है जो अनापेक्षित और मूर्खतापूर्ण है। लेकिन वास्तव में उन विचारों से बिल्कुल अलग जो दंड को अनुचित बनाते हैं जब यह अनुपात से परे हो, तो समान रूप से गैर अनुपातिकदंड के कुछ बहुत ही अवांछनीय व्यावहारिक परिणाम होते हैं। (713-सी-डी|

1.4 अपीलकर्ता के पास बुनियादी मानवता नहीं थी और उसके मानस या मानसिकता का पूरी तरह से अभाव है जो किसी भी सुधार के लिए उत्तरदायी हो सकता है। घटना के समय उसके पास पीड़िता के समान ही एक बच्चा था और फिर भी वह व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे के एक बहुत ही असहाय और असहाय बच्चे की बलि देने और देवता को खुश करने का बहाना करके अपने भाग्य को बढ़ावा देने के लिए सबसे कायरतापूर्ण और विद्रोही तरीके से इस कृत्य की क्रूरता प्रबंधन किया गया है तरीके से लाचार बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया गया. भले ही मासूम बच्चे के असहाय और गिड़गिड़ाते चेहरे और आवाज से अभियुक्त के दिल में दया की कोई झलक न जगी हो, लेकिन जिस गैर-जिम्मेदाराना तरीके से उसने कटे हुए सिर को एक बोरे में ले जाकर तालाब में बिना गलती के फेंक दिया। इससे पता चलता है कि यह कृत्य संकल्पना में अतिशयोक्तिपूर्ण पैशाचिक और निष्पादन में क्रूर था। अभियुक्तों की प्रवृत्ति और ऐसे विद्रोही विचारों को मानने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति को किसी को मारने के आशय के बराबर भी नहीं रखा जा सकता है, लेकिन यह वास्तव में मानवता के खिलाफ अपराध की सीमा पर है, जो न केवल किसी भी सही सोच की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली सबसे बड़ी भ्रष्टता का संकेत है। बल्कि न्यायालय का भी, इस मामले में किए गए अपराध की सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह कृत्य विद्रोही या कायरतापूर्ण नहीं है, तो यह समझ से परे है कि अन्य कृत्य को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, यह प्रश्न है। अंधविश्वास एक विश्वास या धारणा है, जो किसी विशेष चीज़ या परिस्थितियों, घटना या इसी तरह के कारण या ज्ञान या उसके अशुभ महत्व पर आधारित नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से आत्म-प्रशंसा और बर्बरतापूर्ण विचारों से उत्पन्न होता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है।अंधविश्वास किसी भी हत्या के लिए औचित्य प्रदान नहीं कर सकता और न ही करता है, योजनाबद्ध और जानबूझकर की गई हत्या के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। अंधविश्वास का कोई भी रंग अकारण हत्या के पाप और अपराध को नहीं धो सकता, खासकर एक निर्दोष और असहाय बच्चे के मामले में। [713-ई-एच; 714-ए-ई]

1.5. अभियुक्तों की आपराधिक सहज प्रवृत्ति इस तथ्य से स्पष्ट रूप से सामने आती है कि विचारण के समय मानव बलि से जुड़े समान मौजूद थे। हालाँकि परिणाम को अभिलेख पर नहीं लाया जा सका, फिर भी यह तथ्य कि अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध इसी तरह का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए वह विचारण न्यायालय का सामना कर रहा था, को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए यह उपयुक्त मामला नहीं है जहां पृष्ठभूमि के तथ्यों को देखते हुए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। यह एक उदाहरणात्मक और सबसे अनुकरणीय मामला है जिसे दुर्लभतम मामलों में माना जाएगा, जिसमें बिना किसी अपवाद के मृत्युदंड का नियम है और होना भी चाहिए। (714-डी-ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या2003 का 947.

झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.4.2003 सेकोर्ट डी.आर. क्रमांक 3/2002 सीआरएल के साथ। 2002 का ए. नं. 874.

अनिल कुमार मित्तल (ए.सी.)अपीलकर्ता के लिए

ए.टी.एम. रंगरामानुजम, श्रीमती अलका रानी झा और अनिल कुमार झा, प्रतिवादी की ओर से.

न्यायालय का निर्णय

अरिजीतपसायत, जे. द्वारा सुनाया गया। मानवता की छोटी-छोटी बूंदें, जो संयुक्त रूप से मानवता को मानव जाति की प्रेषित इच्छा बनाती हैं, जो प्रकट रूप से सूख गई थीं, जब अपीलकर्ता द्वारा उनकी आपत्ति समृद्धि के लिए देवी काली के सामने 9 साल के एक छोटे बच्चे की बलि दे दी गई जो अभियोजन पक्ष आरोप लगाता है।

"पानी की छोटी बूंदें,
रेत के छोटे कण,
शक्तिशाली महासागर और
सुखद भूमि बनाएं,
दयालुता के छोटे कार्य,
प्यार के छोटे शब्द,
ऊपर के स्वर्ग की तरह पृथ्वी को खुश करने में मदद करें।" जूलियाए.एफ. कैबनीने "लिटिलथिंग्स" में कहा।

मानवता का शांत, उदास संगीत तब शांत हो गया था जब इसे अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा त्याग दिया गया था, जिसे नीचे के न्यायालयों ने पाया है।

11 दिसंबर, 1996 सोमलालबेसरा (अ.सा.-2) के लिए दिल तोड़ने वाला दिन साबित हुआ। उस दिन शाम को उन्होंने अपने बेटे चिरकूबेसरा (बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) को घर से गायब पाया। उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए उसकी तलाश की। जानकारी सामने आई कि अपीलकर्ता द्वारा देवी काली के सामने उसकी बलि दी गई थी। दो अन्य व्यक्तियों, उनकी पत्नी और माँ को भी इस विभत्स हत्या में भागीदार बताया गया था।

अभियोजन पक्ष का मामला बड़ी संख्या में लोगों के सामने अभियुक्त द्वारा की गई न्यायेतरस्वीकारोक्ति, अभियुक्त-अपीलकर्ता के आदेश पर शव की बरामदगी और एक साक्षी के साक्ष्य पर केंद्रित था, जिसने अभियुक्त को साइकिल पर एक बैग ले जाते हुए देखा था, जिसे एक तालाब में फेंक दिया गया था। और बैग को तालाब में फेंक कर अभियुक्त साइकिल से लौट रहा था. तालाब में फेंके गये थैले से कटा हुआ सिर बरामद हुआ. सूचना पुलिस को दी गई, अनुसन्धानकी गई। तीनोंअभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा.द.वि.) की धारा 302 और 20। के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विचारणकिये गए। अपीलकर्ता को दोनों आरोपों के लिए दोषी पाया गया और पहले आरोप के लिए मृत्युदंड और दूसरे आरोप के लिए 7 साल के कठोर कारावास की दंड सुनाई गई। हालाँकि, सह-अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया गया और उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 366 के तहत मृत्युदंड की पुष्टि के लिए विचारण न्यायाधीश यानी प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जामताड़ा द्वारा संदर्भ दिया गया था, जिसे आक्षेपितनिर्णय द्वारा बरकरार रखा गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि हत्या वीभत्स थी,दोषसिद्धि और दंडादेश दोनोंदंड सबसे उपयुक्त दंड थी। उक्त निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपील प्रतिविषय की गई है। अनुमति अनुदत्त करते हुए, आदेश दिनांक 4.8.2003 द्वारा अपील का प्रतिविषयदंड के प्रश्न तक सीमित कर दिया गया था।

विद्वान न्याय मित्र श्री अनिल कुमार मित्तल ने कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार भी हत्या किसी मकसद से नहीं की गई थी। हालाँकि आधुनिक समाज में अंधविश्वास की अपेक्षा नहीं की जाती और उसे प्रोत्साहित नहीं किया जाता, फिर भी अंधविश्वास से भरे माहौल में जन्मे और पले-बढ़े किसी अनपढ़ और आदिवासी को मृत्युदंड नहीं दी जानी चाहिए। उनके अनुसार, आधुनिक प्रवृत्ति सुधार की है और जब किसी मामले में गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों का तुलना पत्र तैयार किया जाता है, तो कम करने वाली परिस्थितियां गंभीर स्थिति से कहीं अधिक होती हैं और इसलिए, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए।

जवाब में, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि 9 साल के बच्चे की सबसे क्रूर और शैतानी तरीके से बलि दी गई।यह एक ऐसा मामला है जो "दुर्लभतम" श्रेणी में आता है और इसलिए, मृत्युदंड देना सही है। यह बताया गया कि यह पहला मामला नहीं है जब अभियुक्त पर इस तरह के अपराध कारितकरने का आरोप लगाया गया है। वास्तव में, जैसा कि अभिलेख से पता चलता है, अपीलकर्ता अपने दो रिश्तेदारों के साथ देवी काली के समक्ष अपने भाई की बलि देकर हत्या कारितकरने के लिए प्रासंगिक समय पर विचारण का सामना कर रहा था।

भा.द.वि. की धारा 302 हत्या के लिए दंड के रूप में मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान करती है। ऐसा करते समय, संहिता न्यायालय को इसके आवेदन के बारे में निर्देश देती है। पिछले तीन दशकों में संहिता में जो परिवर्तन हुए हैं, वे स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि संसद समसामयिकता पर ध्यान दे रही है। आपराधिक विचार और आंदोलन। यह समझना मुश्किल नहीं है कि संहिता में आजीवन कारावास की ओर एक निश्चित झुकाव है। मृत्युदंड को आम तौर पर अमान्य कर दिया जाता है और इसे केवल "विशेष कारणों" से

ही लगाया जा सकता है, जैसा कि धारा 354(3) में दिया गया है। संहिता में एक और प्रावधान है जो महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "विशेष कारण" का भी उपयोग करता है। यह धारा 361 है। संहिता की धारा 360, संक्षेप में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (संक्षेप में पुरानी संहिता") की धारा 562 को पुनः अधिनियमित करती है। धारा 361 जो संहिता में एक नया प्रावधान है, इसे अनिवार्य बनाती है। धारा 360 के प्रावधानों को लागू न करने के लिए न्यायालय को "विशेष कारण" दर्ज करने होंगे।इस प्रकार धारा 361 न्यायालय पर यह कर्तव्य आज्ञापक है कि जहां भी ऐसा करना संभव हो, धारा 360 के प्रावधानों को लागू करे और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो "विशेष कारण*" बताए। धारा 360 के संदर्भ में, धारा 36एल द्वारा विचार किए गए *विशेष कारण" ऐसे होने चाहिए जो न्यायालय को यह मानने के लिए मजबूर करें कि उम्र, चरित्र और पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करने के बाद अपराधी को सुधारना और पुनर्वास करना असंभव है। अपराधी और वे परिस्थितियाँ जिनमें अपराध कारितकिया गया था, यह विधायिका द्वारा कुछ संकेत है कि अपराधियों का सुधार और पुनर्वास, न कि केवल निवारण, अब हमारे देश में आपराधिक न्याय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है धारा 354(3) दोनों एक ही समय में कानून की किताब में शामिल हो गए हैं और वे अपराध विज्ञान में नए रुझानों की विधायिका द्वारा स्वीकार्यता की उभरती तस्वीर का हिस्सा हैं, इसलिए यह मानना गलत नहीं होगा अपराधी की उम्र, चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य परिस्थितियों से पता चलता है और अपराधी की सुधार की क्षमता को आवश्यक रूप से दी जाने वाली दंड का निर्धारण करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। विशेष कारणों का इन कारकों से कुछ संबंध होना चाहिए, आपराधिक न्याय जटिल मानवीय समस्याओं और विविध मनुष्यों से संबंधित है। एक न्यायाधीश को अपराधी के व्यक्तित्व को परिस्थितियों, स्थितियों और प्रतिक्रियाओं के साथ संतुलित करना होता है और लगाए जाने वाले उचित दंड का चयन करना होता है।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पुरानी संहिता की धारा 367(5) में संशोधन से पहले, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 (26 ए.एफ.1955) द्वारा, जो 1.1.1956 को लागू हुआ, किसी के लिए दोषसिद्धि पर मृत्युदंड वाले अपराध में, अगर न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्यु के साथ-साथ किसी अन्य दंड की सजा सुनाई है, तो मृत्युदंड क्यों नहीं दी गई, इसका कारण निर्णय में बताना होगा। 1955 के अधिनियम 26 द्वारा पुरानी संहिता की धारा 367(5) में संशोधन के बाद स्थिति स्पष्ट है कि सामान्य जुर्माना आजीवन कारावास है। इसे ऐसी परिस्थितियों की उपस्थिति में दिया जा सकता है जो अपराध की गंभीरता को कम कर देती हैं। संशोधन के बाद मामला न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है। हालाँकि, न्यायालय को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, और अपने विवेक से दोनों में से जो भी दंड दी जाए, उसके लिए अपने कारण बताने चाहिए। इसलिए, पूर्व नियम कि हत्या के लिए सामान्य दंड मृत्युदंड है, अब लागू नहीं है और अब यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि वह इस धारा में निर्धारित दो दण्डो में से किसी एक को पारित करे; लेकिन न्यायाधीश दोनों में से जो भी दंड सुनाए, उसे विशेष दंड देने के लिए अपने कारण बताने होंगे। पुरानी संहिता की धारा 367(5) में संशोधन भा.द.वि.के तहत दंड को विनियमित

करने वाले कानून को प्रभावित नहीं करता है। यह संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है और अब न्यायालयों को मृत्युदंड न देने के

कारणों को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है; लेकिन वे कम दंड को प्राथमिकता देते हुए ठोस न्यायिक विचारों से पीछे नहीं हट सकते।

संहिता की धारा 354(3) 1.4.1974 से ठीक पहले लागू पुरानी संहिता की अंतर्निहित विधायी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसके अनुसार हत्या के लिए प्रदान की गई मृत्युदंड या आजीवन कारावास की दोनों वैकल्पिक सजाएँ सामान्य थीं। अब, संहिता की धारा 354(3) के तहत हत्या के लिए सामान्य दंड आजीवन कारावास है और मृत्युदंड एक अपवाद है। न्यायालय को दी गई दंड के कारणों को बताने की आवश्यकता है और मृत्युदंड के मामले में "विशेष कारणों" को बताने की आवश्यकता है, यानी, केवल विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ ही मृत्युदंड को पारित करने की गारंटी देंगी। संहिता में इन क्रमिक विधायी परिवर्तनों के आलोक में 1955 के अधिनियम 26 और फिर 1974 के अधिनियम 2 द्वारा किए गए संशोधन से पहले के न्यायिक निर्णयों को समझना होगा।

एडिगाअनम्मा बनाम स्टेट ऑफ एपी, [एल1974]4 एससीसी 443 में इस न्यायालय ने कहा है: (एस.सी.सी.पी.पी. 453-54, पैरा 26)

"26 आइए हम वर्तमान में भारतीय कानून के तहत मृत्युदंड के विरुद्ध सकारात्मक संकेतकों को स्पष्ट करें। जहां हत्यारा बहुत छोटा या बहुत बूढ़ा है, वहां क्षमादान या दंडात्मक न्याय उसकी मदद करता है। जहां अपराधी सामाजिक-आर्थिक, मानसिक या दंडात्मक मजबूरियों से पीड़ित है, जो कानूनी अपवाद को आकर्षित करने या अपराध को कम करने के लिए अपर्याप्त है। , न्यायिक परिवर्तन की अनुमति अन्य सामान्य सामाजिक दबावों के कारण होती है, जिसके लिए न्यायिक नोटिस की आवश्यकता होती है। विशेष मामलों में, प्रभाव को कम करने के साथ, कम जुर्माना लगा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में असाधारण विशेषताएं, जैसे कि मृत्युदंड अपराधी के सिर पर लटका दी गई है। कष्टदायी रूप से लंबा, न्यायालय को दयालु होने के लिए राजी कर सकता है।इसी तरह, यदि अपराध में शामिल और इसी तरह के अन्य लोगों को आजीवन कारावास का लाभ मिला है या यदि अपराध केवल रचनात्मक है, जो धारा 302 के तहत है, धारा 149 के साथ पढ़ा जाता है, या फिर अभियुक्त ने किसी अन्य के उकसावे के तहत, बिना पूर्वचिन्तन के अचानक कार्य किया है, शायद न्यायालय मानवीय रूप से जीवन का विकल्प चुन सकती है, यहां तक कि जहां एक उचित कारण या पत्नी की बेवफाई के वास्तविक संदेह ने अपराधी को अपराध में धकेल दिया। दूसरी ओर, प्रयुक्त हथियार और उनके प्रयोग का तरीका, अपराध की भयावह विशेषताएं और पीड़ित की असहाय, असहाय स्थिति और इसी तरह की चीजें, एक कठोर दंड के लिए कानून का दिल मजबूत करती हैं। हम स्पष्ट रूप से ऐसी सभी स्थितियों को न्यायिक कंप्यूटर में दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि वे एक अपूर्ण और उतार-चढ़ाव वाले समाज में ज्योतिषीय रूप से असंभव हैं। जीवन या मृत्यु पर एक कानूनी नीति को तदर्थ मनोदशा या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है और इसलिए हमने प्रतिशोधात्मक

क्रूरता को त्यागकर, निवारक पंथ में संशोधन करने और अत्यधिक और अपरिवर्तनीय दंड के खिलाफ प्रवृत्ति पर जोर देने के लिए, यथासंभव हद तक आपत्ति करने की कोशिश की है। जीवन से बाहर कर देना।

" बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1980] 2 एससीसी 684 में यह देखा गया है कि: (एससीसी पृष्ठ 751, पैरा 209)

*मानव जीवन की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता प्रतिरोध को दर्शाती है कानून के माध्यम से किसी की जान लेना।

दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों को छोड़कर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जब वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद हो। विकल्प अपनाने से पहले गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच उचित संतुलन बनाना होगा। इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उत्तर दिए जा सकते हैं, (ए) क्या इसमें कुछ असामान्य है। ऐसा अपराध जो आजीवन कारावास की दंड को अपर्याप्त बनाता है और कहता है मृत्युदंड की दंड के लिए?; और (बी) क्या अपराध की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अभियुक्त के पक्ष में शमन करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी मृत्युदंड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है?

एक और निर्णय जो मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, [19831] 3 एससीसी 470 में मृत्युदंड के प्रश्न पर प्रकाश डालता है।

मच्छी सिंह (सुप्रा) और बचन सिंह (सुप्रा) मामलों में इस प्रश्न पर विचार करते समय कि क्या मामला दुर्लभतम श्रेणी का है, ध्यान में रखे जाने वाले दिशानिर्देशों का संकेत दिया गया था।

मच्छी सिंह मामले (सुप्रा) में यह देखा गया था: (एससीसी पृष्ठ 489, पैरा 39)

"दुर्लभ से दुर्लभतम" मामले को निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण के रूप में निम्नलिखित प्रश्न पूछे और उत्तर दिए जा सकते हैं जिसमें मृत्युदंड दी जा सकती है: -

(ए) क्या उस अपराध में कुछ असामान्य है जो आजीवन कारावास की दंड को अपर्याप्त बनाता है और मृत्युदंड की मांग करता है?

(बी) क्या अपराध की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में बोलने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी मृत्युदंड देने के साथ कोई विकल्प नहीं है?

बचन सिंह मामले (सुप्रा) से उभरे निम्नलिखित दिशानिर्देशों को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर लागू करना होगा जहां मृत्युदंड देने का सवाल उठता है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 489, पैरा 38): -

(i) चरम अत्यधिक दोषी होने के गंभीर मामलों को छोड़कर मृत्युदंड की दंड देने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले 'अपराध' की परिस्थितियों के साथ-साथ 'अपराधी' की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है

(iii) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड

अपवाद। मृत्युदंड केवल तभी दी जानी चाहिए जब आजीवन कारावास अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से अपर्याप्त दंड प्रतीत होती है, और प्रदान की जाती है, और केवल प्रदान की जाती है, बशर्ते, अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास की दंड देने का विकल्प विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

(iv) गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों की एक तुलना पत्र तैयार करना होगा और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होगा और गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा। विकल्प का प्रयोग किया जाता है.

दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में जब समुदाय की सामूहिक चेतना इतनी सदमे में होती है कि वह न्यायिक शक्ति केंद्र के धारकों से मृत्युदंड की वांछनीयता या अन्यथा के संबंध में उनकी व्यक्तिगत राय के बावजूद मृत्युदंड देने की अपेक्षा करेगा, तो मृत्युदंड दी जा सकती है। समुदाय निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी भावना का विचार कर सकता है:

(1) जब हत्या अत्यंत क्रूर, वीभत्स, शैतानी, विद्रोही या कायरतापूर्ण तरीके से की गई हो ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा हो।

(2) जब हत्या किसी ऐसे आशय से की जाती है जो पूरी तरह से भ्रष्टता और नीचता को दर्शाता है; जैसे पैसे या इनाम के लिए भाड़े के हत्यारे द्वारा हत्या या किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए निर्मम हत्या, जिस पर हत्यारा प्रभुत्वशाली स्थिति में है या विश्वास की स्थिति में है, या हत्या विश्वासघात के लिए की गई है मातृभूमि.

(3) जब अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय आदि के किसी सदस्य की हत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं की जाती है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में की जाती है, जिससे सामाजिक क्रोध पैदा होता है, या वधू विवाह या दहेज हत्या के मामलों में या जब हत्या क्रम में की जाती है एक बार फिर दहेज वसूलने के लिए पुनर्विवाह करना या मोह के कारण किसी अन्य महिला से विवाह करना।

(4) जब अपराध अनुपात में बहुत अधिक हो। उदाहरण के लिए, जब कई हत्याएं की जाती हैं, उदाहरण के लिए एक परिवार के सभी या लगभग सभी सदस्यों की या किसी विशेष जाति, समुदाय या इलाके के बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं की जाती हैं।

(5) जब हत्या का शिकार एक मासूम बच्चा, या एक असहाय महिला या बूढ़ा या अशक्त व्यक्ति हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिसका हत्यारा प्रभुत्वशाली स्थिति में हो या कोई सार्वजनिक व्यक्ति हो जिसे आमतौर पर समुदाय द्वारा प्यार और सम्मान किया जाता हो।

यदि उपरोक्त प्रस्तावों के आलोक में सभी परिस्थितियों का समग्र वैश्विक दृष्टिकोण लिया जाए और दुर्लभतम मामलों के परीक्षण के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान में रखा जाए, तो मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मृत्युदंड दी जा सकती है। वारंट है, न्यायालय ऐसा करने के लिए आगे बढ़ेगी।

जब अपराध की गंभीरता और पर्याप्त दंड देने का सवाल विचार के लिए आता है तो एक दोषी जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहता है।मानव जाति प्राकृतिक अवस्था से सभ्य समाज की ओर स्थानांतरित हो

गई है और यह अब बहुसंख्यकों की भौतिक राय नहीं है जो किसी नागरिक को दोषी ठहराकर और उसे कारावास की दंड देकर उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है। मुकदमे में दोषसिद्धि के बाद दंड देना, कानून के शासन से जुड़ी एक प्रणाली है, जो पक्षों की पर्याप्त सुनवाई के बाद न्यायालय कक्ष में शांत विचार-विमर्श का परिणाम है, अभियुक्तों के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, अभियोजन पक्ष को एक अवसर दिया जाता है।

अपनी बेगुनाही साबित करके आरोपों को पूरा करना। यह गहन विचार-विमर्श और जानकार व्यक्ति यानी न्यायाधीश द्वारा सामग्री की जांच का परिणाम है जो मुकदमे के निर्धारण की ओर ले जाता है।

अपराध और दंड के बीच अनुपात का सिद्धांत न्यायसंगत रेगिस्तान का सिद्धांत है जो हर उचित आपराधिक दंड की नींव के रूप में कार्य करता है। आपराधिक न्याय के सिद्धांत के रूप में यह उस सिद्धांत से शायद ही कम परिचित या कम महत्वपूर्ण है कि केवल दोषियों को ही दंडित किया जाना चाहिए। वास्तव में, यह आवश्यकता कि दंड असंगत रूप से बड़ी न हो, जो न्यायसंगत रेगिस्तान का परिणाम है, उसी सिद्धांत से तय होती है जो अपराधी के लिए योग्य से अधिक किसी भी दंड के लिए निर्दोष को दंड देने की अनुमति नहीं देता है। आचरण बिना दोष के दण्ड है। आपराधिक कानून आम तौर पर प्रत्येक प्रकार के आपराधिक आचरण की दोषीता के अनुसार दायित्व निर्धारित करने में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करता है। यह आम तौर पर न्यायाधीश को किसी निर्णय पर पहुंचने में कुछ महत्वपूर्ण विवेक की अनुमति देता है। प्रत्येक मामले में दंड, संभवतः ऐसे वाक्यों की अनुमति देने के लिए जो प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों द्वारा उठाए गए दोषीता के अधिक सूक्ष्म विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं, न्यायाधीश संक्षेप में पुष्टि करते हैं कि दंड हमेशा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए, फिर भी व्यवहार में दंड एं बड़े पैमाने पर अन्य विचारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं कभी-कभी यह अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकताएं होती हैं जो किसी दंड को उचित ठहराने के लिए पेश की जाती हैं, कभी-कभी उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयता, और कभी-कभी उसके अपराध के दुखद परिणाम भी अनिवार्य रूप से रेगिस्तान से विचलन का कारण बनते हैं दंड का आधार और स्पष्ट अन्याय के मामले बनाएं जो गंभीर और व्यापक हों।

अपराध और दंड के बीच अनुपात एक ऐसा लक्ष्य है जिसका सैद्धांतिक रूप से सम्मान किया जाता है, और ग़लत धारणाओं के बावजूद, यह दण्डों के निर्धारण में एक मजबूत प्रभाव रखता है। किसी भी गंभीर अपराध के लिए अधिकतम गंभीरता के दंड से कम कुछ भी सहनशीलता का एक उपाय माना जाता है जो अनुचित और मूर्खतापूर्ण है। लेकिन वास्तव में उन विचारों के अलावा जो अपराध के अनुपात से बाहर होने पर दंड को अनुचित ठहराते हैं, समान रूप से अनुपातहीन दंड के कुछ बहुत ही अवांछनीय व्यावहारिक परिणाम होते हैं।

इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि अपीलकर्ता के पास बुनियादी मानवता नहीं थी और उसके पास मानस या मानसिकता का पूरी तरह से अभाव है जो किसी भी सुधार के लिए उत्तरदायी हो सकता है। घटना के समय उसके पास पीड़ित के समान उम्र का एक बच्चा था और फिर भी उसने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे के एक बहुत ही असहाय और असहाय बच्चे की बलि देने और खुश होने का नाटक करके अपने भाग्य को बढ़ावा देने के लिए सबसे घृणित और विद्रोही तरीके से

शैतानी योजना बनाई। देवता. इस कृत्य की क्रूरता उस वीभत्स और विद्रोही तरीके से और भी बढ़ जाती है जिसमें असहाय बच्चे का सिर काट दिया गया था। भले ही मासूम बच्चे के असहाय और गिड़गिड़ाते चेहरे और आवाज ने अभियुक्त के दिल में दया की कोई भावना नहीं जगाई, लेकिन जिस गैर-जिम्मेदाराना तरीके से उसने कटे हुए सिर को एक बोरे में ले जाकर बिना गलती के तालाब में फेंक दिया। इससे पता चलता है

कि यह कृत्य संकल्पना में अतिशयोक्तिपूर्ण और निष्पादन में क्रूर था। अभियुक्तों की प्रवृत्ति और उस मामले में ऐसे विद्रोही विचारों को मानने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति को एक के बराबर भी नहीं रखा जा सकता है किसी को मारने का आशय है, लेकिन वास्तव में मानवता के खिलाफ अपराध की सीमा पर है, जो सबसे बड़ी भ्रष्टता का सूचक है, जो किसी भी सही सोच वाले व्यक्ति के साथ-साथ कानून की नययालायो की अंतरात्मा को भी झकझोर देता है। इस मामले में किए गए अपराध की सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह कृत्य विद्रोही या कायरतापूर्ण नहीं है, तो यह समझ से परे है कि अन्य कृत्य को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, यह प्रश्न है। अंधविश्वास एक विश्वास या धारणा है, जो तर्क या ज्ञान, किसी विशेष चीज या परिस्थिति, घटना या उसके जैसे अशुभ महत्व पर आधारित नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से आत्म-प्रशंसा और बर्बरतापूर्ण विचारों से उत्पन्न होता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है। अंधविश्वास किसी भी हत्या का औचित्य प्रदान नहीं कर सकता और न ही प्रदान करता है, योजनाबद्ध और जानबूझकर की गई हत्या के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। अंधविश्वास का कोई भी रंग अकारण हत्या के पाप और अपराध को नहीं धो सकता, खासकर एक निर्दोष और असहाय बच्चे के मामले में।

अभियुक्तों की आपराधिक प्रवृत्ति इस तथ्य से स्पष्ट रूप से सामने आती है) कि परीक्षण के समय मानव बलि से जुड़े समान विचारण के समय उपलब्ध थे। हालाँकि परिणाम को अभिलेख पर नहीं लाया जा सका, फिर भी इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध भी इसी तरह का आरोप लगाया गया था जिसके लिए वह मुकदमे का सामना कर रहा था। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ऊपर जोर दिए गए पृष्ठभूमि तथ्यों को देखते हुए, हमें नहीं लगता कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हमारे विचार में यह एक उदाहरणात्मक और सबसे अनुकरणीय मामला है जिसे दुर्लभतम मामलों में माना जाएगा, जिसमें बिना किसी अपवाद के मृत्युदंड का नियम है और होना भी चाहिए। अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

हम श्री अनिल कुमार मित्तल, विद्वान न्याय मित्र और श्री ए.टी.एम. द्वारा दी गई उचित प्रस्तुति और सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रंगरामानुजम ने मृत्युदंड के प्रश्न से जुड़े कानूनी सिद्धांतों पर बहुत ही कुशलता से प्रकाश डाला।
बी.एस.अपील खारिज किया गया ।

<u>यह अनुवाद किरण शंकर मिश्रा, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।</u>